

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-२

देहरादून: दिनांक-२६ दिसम्बर, २००७

विषय: नगर पालिका परिषद, किंच्चा के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष-२००५-०६ में स्वीकृत कार्यों की अवशेष धनराशि की चालू वित्तीय वर्ष २००७-०८ में स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या २६२/V-श.वि.-०६-१८९(सा.)/२००५, दिनांक ०६.२.२००६ का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर पालिका परिषद, किंच्चा जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत यारह कार्यों हेतु रु०-३५६.५० लाख की लागत के आगणन के विपरीत रु०-३५४.२८ लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या ८०१/V-शा०वि०-०६-६६(सा०)/०३ दिनांक २९ मार्च, २००६ के द्वारा रु० २३३.९४ लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। नगर पालिका द्वारा अपने पत्रांक १६६/अवस्थापना निधि/२००७ दिनांक ८-१०-२००७ के माध्यम से प्रस्तुत किये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र में उक्त शासनादेश के द्वारा स्वीकृत कार्यों के क्रमांक-१२ के कार्य 'मैटाडोर स्टैण्ड निर्माण रथल' में विवाद होना अवगत कराये जाने के कारण उक्त कार्य की स्वीकृति को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक ६-२-२००६ के क्रमांक-१२ के उक्त कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि रु० १०.६५ लाख (रु० दस लाख पैसठ हजार मात्र) को उक्त शासनादेश दिनांक ६-२-२००६ के माध्यम से स्वीकृत अन्य कार्यों हेतु स्वीकृति अवशेष धनराशि रु०-१०९.६९ लाख (एक करोड़ नौ लाख उन्हत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष स्वीकृत करते हुए रु० १०.६५ लाख उक्त योजना की धनराशि के लिए रवीकृत धनराशि को अन्य चालू कार्यों पर तथा शेष १०९.६९ लाख के विपरीत वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक रो रु. ८०.०० लाख (रुपये अस्सी लाख मात्र) की धनराशि के ब्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

१. उक्त धनराशि रु. ८०.०० लाख (रुपये अस्सी लाख मात्र) आपके द्वारा आहरित कर संबंधित नगर पालिका को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, जो शासनादेश की शर्त पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे।
२. शासनादेश संख्या २६२/V-श.वि.-०६-१८९(सा.)/२००५, दिनांक ०६.२.२००६ में उल्लिखित अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
३. सम्बन्धित कार्यदायी संरथा द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
४. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेतर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
५. स्वीकृत धनराशि का इसी वित्तीय वर्ष में उपयोग करते हुए कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।
६. कार्यों की समयवस्था एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

क्रमशः

7. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी।
8. मुख्य सचिव महोदय, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV.219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगमन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-03-2008 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

2- उक्त के संबंध में होने वाला व्यव वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-रथानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05- नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा००३०- 528/XXVII(2)/2007, दिनांक- 18 दिसम्बर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

मवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव।

स०-३८७ (१) / IV-श०वि०-०७, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी/ नगर विकास मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
5. गिलाधिकारी, उधमसिंह नगर।
6. वरिष्ठ कोपाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी०ओ० में इसे शामिल करें।
9. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, किंचा।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(गोपाल कृष्ण द्विवेदी) अपर सचिव।